- 20th Year
- Issue: 137
- 20.09.2026 (SUNDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

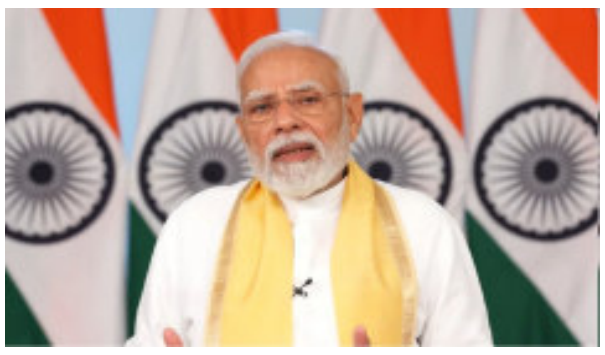

पीएम मोदी ने रोजगार मेला में बांटे ५१ हजार नियुक्ति पत्र, कहा-विकसित भारत ही मुख्य लक्ष्य

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 20वें रोज़गार मेले में अलग-अलग सरकारी संगठनों में नए नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मोदी ने कहा कि देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इन उत्सवों के बीच, आज का दिन हज़ारों परिवारों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आया है। आज देश भर में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं... आप भारत सरकार से ऐसे समय में जुड़ रहे हैं जब देश एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है—और वह लक्ष्य है 2047 तक %विकसित भारत% का निर्माण करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रयास में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। सरकार का हिस्सा होने के नाते, आपके हर फ़ैसले से %विकसित भारत% और %आत्मनिर्भर भारत% के अभियानों को लगातार मज़बूती मिलनी चाहिए। युवा होने के नाते, अपने

साथी युवाओं के प्रति आपकी एक विशेष ज़िम्मेदारी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, उद्यमियों और युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ ही दिन पहले ब्रिज़्स (क्क्क्ष्ट्स) शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ब्रिज़्स का सहयोग केवल सरकारों तक ही सीमित न रहे; बल्कि हमारे उद्यमी, किसान, महिलाएँ और युवा—सभी इस साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसी सोच के साथ ब्रिज़्स कनेज़्ट और %ब्रिज़्स स्स्स्ध सहयोग पोर्टल जैसी पहल शुरू की गई हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, भारत ने लगभग 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (स्त्र्ञ) किए हैं। ये स्त्र्ञ हमारे युवाओं के लिए मौके के नए दरवाज़े खोल रहे हैं। ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट हमारे उद्यमियों के लिए नई पार्टनरशिप का रास्ता बनाते हैं, नए बाज़ारों तक पहुँच दिलाते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर के नए अवसर पैदा करते हैं। भारत सरकार लगातार युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान दे रही है—चाहे वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने की कोशिशें हों। हमारा मकसद यह पक्का करना है कि हमारे युवाओं की शिक्षा और स्किल्स बदलती हुई इकॉनमी की ज़रूरतों के साथ कदम मिलाकर चलें। इसका एक उदाहरण क्क्रस्श्ज्ञ स्कीम है; ?60,000 करोड़ के निवेश से 1,000 सरकारी ढ्ढञ्ज्ञ को मॉडर्न बनाया जा रहा है, और इस प्रक्रिया में इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी भी पक्की की जा रही है।उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की क्षमता की एक और झलक हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और भारतीय स्टार्टअप की कहानी अब सिर्फ़ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है; लगभग आधे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। इसका मतलब है कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा भारत की नई अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। छोटे शहरों के युवा अपने आइडिया पर काम कर रहे हैं, नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं और दूसरों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेज़्टर में भी रोज़गार के अवसरों को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें

मोदी ने कहा कि इसी सोच के साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट वाली %प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना% शुरू की गई है। इस योजना से लगभग 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्कफोर्स (कामकाजी आबादी) में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत, सरकार अपनी पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को ?15,000 तक का इंसेंटिव दे रही है, साथ ही नए रोज़गार के अवसर पैदा करने वाले नियोक्ताओं (एज़्प्लॉयर्स) को भी इंसेंटिव दे रही है। दूसरे शज़्दों में, सरकार देश में रोज़गार बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। युवाओं के लिए नए अवसर तभी पैदा होते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेज़्टर का विस्तार होता है।

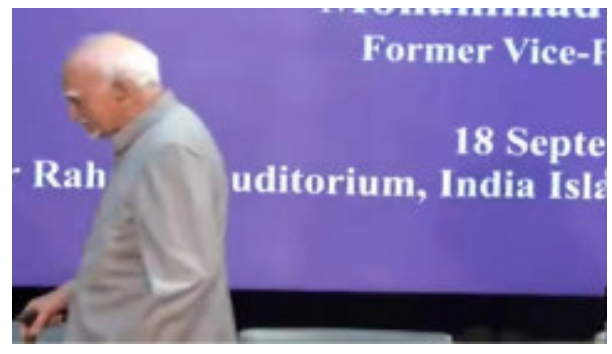

भारत को खतरा वामपंथ से नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है-हामिद अंसारी

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। हामिद अंसारी वो शज़्स हैं जिन पर ईरान का राजदूत रहते हुए आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की जान खतरे में डाली थी। रॉ के कुछ पूर्व अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी पर लगे आरोपों की जांच कराने तक की मांग कर चुके हैं। हामिद अंसारी वो शज़्स हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले महमूद गजनवी को भारतीय लुटेरा बोलकर भारत के ही इतिहास को कलंकित करने का काम किया। अब इन्हीं हामिद अंसारी ने बयान दिया है कि भारत को खतरा कज़्युनिज्म यानी वामपंथ से नहीं है बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है। कितनी आसानी से हिंदुओं को सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है। हामिद अंसारी ने बताया कि एक किताब में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को एक बैठक में चेतावनी देते हुए ऐसे शज़्द बोले थे।

यानी नेहरू ने कहा था कि वामपंथी नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथियों से भारत को खतरा है। चाव लेकर यही बात हामिद अंसारी बता रहे हैं। हामिद अंसारी का यह बयान सुनकर कई लोगों का कहना है कि भारत में अगर हिंदू मेजॉरिटी में नहीं होते तो आज भारत में संविधान से ऊपर शरिया होती। जो लोग आज सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं उन्हें उल्टा लटका दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी लिखते हैं कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का धर्मनिरपेक्षता वाला यह पैमाना कितना पाखंड पूर्ण है। यह शर्म की बात है कि यह हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी की यह छटपटाहट नई नहीं है। इवेंट का नाम 'रिमेंबरिंग अ पॉलीमैथ- द लाइफ एंड टाइज़्स ऑफ अज़्दुल गफ़ूर नूरानी' था। यह आयोजन नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ। अंसारी ने एजी नूरानी की 2019 में प्रकाशित किताब 'द RSS: अ मेनेस टू इंडिया' का जिक्र किया। उन्होंने नागरिक राष्ट्रवाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते रुझानों पर चिंता जताई। अंसारी ने कहा कि नूरानी की यह किताब शायद उनकी आखिरी बड़ी किताब थी। उन्होंने इसे आकार और कंटेंट, दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। अंसारी के मुताबिक, नूरानी ने किताब की भूमिका में दो उर्दू शेरों के जरिए अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि नूरानी ने किताब में अपने वैचारिक उद्देश्य को छिपाने की कोशिश नहीं की। अंसारी ने पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया के दस्तावेज में दर्ज जवाहरलाल नेहरू के बयान का हवाला दिया। यह बयान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक से जुड़ा था। अंसारी ने कहा, नेहरू ने चेतावनी दी थी कि भारत को असली खतरा कज़्युनिज्म से नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था। 10 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के कार्यकाल का अंतिम दिन था।

सिस्टम को सवाल पूछने वाले छात्र नहीं, सिर्फ अंधभक्त चाहिए-राहुल गांधी

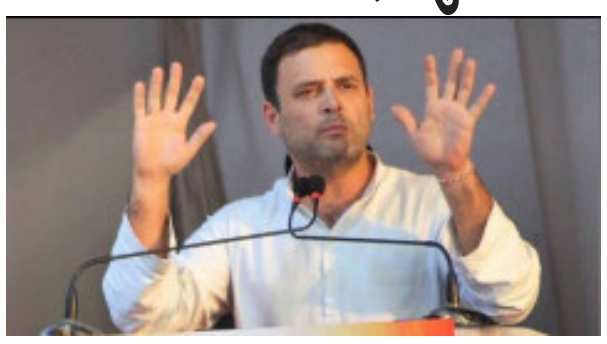

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों को लगता है कि जिस व्यवस्था को उनकी मदद और सुरक्षा के लिए, और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रक्षा के लिए बनाया गया है, वही उन पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ़ है। यह सिस्टम ज़्या है? इस सिस्टम की कई परतें हैं। सबसे ऊपर छह लोग बैठे हैं जो इसे चलाते हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी—वह डराने-धमकाने, छात्रों की पिटाई, कील लगी लाठियों के इस्तेमाल और पैलेट गन चलाने जैसे काम संभालते हैं; अमित शाह जी इसे चलाते हैं; वह इसे लागू करने वाले (en-forcer) हैं। ये हैं अजीत डोभाल जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अनौपचारिक बातचीत में वह कहते हैं कि भारत को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ 500 लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी है। उन्होंने भारत के टेलीफ़ोन, WhatsApp और Facebook कज़्युनिकेशन पर कंट्रोल कर लिया है; वह फ़ोन टैपिंग करवाते हैं और जानकारी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीच में मोहन भागवत जी हैं, जो विचारधारा का काम देखते हैं; उनके संगठन को स्कूल, कॉलेज और संस्थान चलाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मिलते हैं। फिर, एक तरफ़ अडानी जी हैं और दूसरी तरफ़ अंबानी जी... सिस्टम ने हर संस्थान में अपने ही लोगों को बिठा रखा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को छात्रों से खतरा महसूस होता है। ज़्यों? ज़्योंकि छात्र सवाल पूछते हैं। एक छात्र पूछता है कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन कैसे बना। एक छात्र पूछता है कि कैसे दो लोगों ने भारत के पूरे बिज़्नेस जगत पर कज़्ज़ा कर लिया। एक छात्र पूछता है कि न्यायपालिका और दूसरी संस्थाएं अपना काम करने में ज़्यों नाकाम रहती हैं, या चुनाव आयोग अपनी ज़िज़्मेदारियां ज़्यों नहीं निभा रहा है। इसीलिए सिस्टम को छात्र नहीं चाहिए; उसे %अंधभक्त% चाहिए। अंधभक्त, छात्र का ठीक उल्टा होता है। जहाँ छात्र सवाल पूछता है और जिज्ञासु रहता है, वहीं अंधभक्त अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। जहाँ छात्र निडर होता है, वहीं अंधभक्त डरपोक होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अंधभक्त कहते हैं कि विकास की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन अंधभक्त कभी सवाल नहीं पूछते। अंधभक्त कभी यह नहीं पूछेगा कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों की हालत ऐसी ज़्यों हो गई है।

दिशा सालियान मामले में संजय राउत का आरोप, ठाकरे परिवार को फंसाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल

मुंबई १९/०९ (संवाददाता): शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के मामले में ठाकरे परिवार के खिलाफ कीचड़ उछालने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल "कठपुतली" के रूप में किया जा रहा है। राउत ने नारायण राणे परिवार, खासकर उनके बेटे एवं महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे, पर दिशा सालियान मामले में शिवसेना (उबाठा) के नेता आदित्य ठाकरे का नाम "घसीटने" को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले

20 वर्षों में कणकवली में हुई सभी हत्याओं के लिए राणे परिवार को गिरज़्तार किया जाना चाहिए। राउत ने किसी का नाम लिए बिना एक सवाल के जवाब में कहा, "आप दूसरों के हाथों की कठपुतली हैं और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं।" राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि सतीश सालियान को किसी के द्वारा "नियंत्रित" किया जा रहा है। राउत ने दावा किया, "वह (दिशा के पिता सतीश सालियान) छह साल पहले इस बात से संतुष्ट थे कि यह हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी।" उन्होंने कहा कि जब ठाकरे परिवार कुछ अच्छा काम करता है तो ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया जाता है और इसके इर्द-गिर्द एक तंत्र खड़ा कर दिया जाता है। राउत ने कहा, "आप आदित्य का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो दिशा को जानते तक नहीं थे।" उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि ठाकरे परिवार के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान के लिए धन कौन मुहैया करा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

डूसू चुनाव में एबीवीपी का दबदबा, केंद्रीय पैनल के तीन पदों पर जीत दर्ज की

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में केंद्रीय पैनल के चार पदों में से तीन पर जीत के बाद शनिवार को एबीवीपी समर्थकों ने कला संकाय के बाहर जीत का जश्न मनाया और इस दौरान पूरा क्षेत्र नारों से गूंज उठा। परिणामों की घोषणा के बाद संकाय के बाहर जुटे छात्र संगठन के समर्थकों ने पार्टी के झंडे लहराए और हवा में पर्चे उछाले। उज़्री परिसर स्थित इस स्थल पर दोपहर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उज़्मीदवारों और छात्र संगठनों को परिणाम घोषित होने के बाद सड़कों, परिसर और छात्रावासों में विजय जुलूस निकालने से परहेज करने का निर्देश दिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने डूसू के चुनाव में केंद्रीय पैनल के चार पद में से तीन पर जीत दर्ज की, जबकि एनएसयूआई का टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उज़्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी के उज़्मीदवार यश डबास ने अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के विजय शंकर मीणा को 2,053 वोटों के अंतर से हराया।

दिल्ली में ७५ लाख नाम कटने का खतरा! एसआईआर पर सुको की सुनवाई २१ को

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। अब इस प्रक्रिया के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। जिस तरह दिल्ली में एसआईआर के तहत 47 लाख नाम हटाए गए और 33 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। उसे लेकर विवाद छिड़ गया है। चुनाव आयोग सवालों से घिर गया। कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। तो ज़्या फिर सवालों से घिरा चुनाव आयोग? वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग कटघरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नई याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जहरी ने चुनाव आयोग पर नियमों का पालन ना करने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किए जाने पर याचिकाकर्ता का दावा है कि यह नाम वेबसाइट पर नहीं दिखाए गए और उन्हें नोटिस की वजह भी नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में मतदाता सूची से करीब 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही यह भी साफ नहीं किया गया कि किन आधारों पर उनके नामों पर सवाल उठाए गए। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि किन मतदाताओं के रिकॉर्ड में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियां पाई गई और किन लोगों को

अनमैप्ड की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल दिल्ली में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के बाद 31 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट प्रकाशित किया गया जिसमें पिछली बार के 1 करोड़ 45 लाख लोगों की सूची से करीब 47 लाख नाम काट दिए गए और अब लगभग 33 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैप्ड के आधार पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। याचिका के मुताबिक, दिल्ली की 31 अगस्त की ड्राफ़्ट सूची में 97,53,577 वोटर शामिल हैं। वहीं 47,56,722 नाम ड्राफ़्ट सूची में नहीं हैं। 13,79,785 वोटर्स को %नो मैपिंग% और 19,33,134 को %लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज% के आधार पर नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है। नामगाइड खोजें

एसआईआर के दौरान बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और सेज़्स वर्कर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। दिल्ली के 13 जिलों में ये कैंप 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक डीयूएसआईबी के नाइट शेल्टर और दूसरे चिन्हित स्थानों पर लगाए जाएंगे। कैंप में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को पहचान, पते और जरूरी डॉज़्यूमेंट देने में कई बार परेशानी होती है।स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स्ढ्ढक्र) के तहत जारी ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में एक और जीवित शज़्स का नाम डेथ लिस्ट में डालने का मामला सामने आया है। लाल गुज़्बद के रहने वाले कुन्ने लाल (60) ने विडियो जारी कर कहा है कि वो जीवित है। वह 50 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं और पिछले चुनावों में वोट देते रहे हैं। कुन्ने लाल की नातिन अनीता ने बताया कि दादाजी ठीक हैं। परिवार में पिता-माता, भाई और उनकी पत्नी और बाकी सभी के नाम ड्राफ़्ट लिस्ट में हैं, सिर्फ दादा का नाम नहीं है। दो दिन पहले एनजीओ में काम करने वाली एक महिला ने परिवार को बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अनीता के मुताबिक, जब एन्युमरेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, तब कुन्ने लाल गांव में थे। परिवार ने इसकी जानकारी दी थी। अधिकारी ने कहा था कि उनका फॉर्म बाद में भरवा लिया जाएगा लेकिन कोई फॉर्म भरवाने नहीं आया। अब पता चला कि उनका नाम डेथ लिस्ट में डाल दिया गया है। दिल्ली में स्ढ्ढक्रके तहत ज़्लेम और ऑज़्जेज़्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए करीब 47.5 लाख वोटर्स की तुलना में नाम जुड़वाने के लिए आने वाले आवेदनों की रज़्तार अभी भी धीमी है। 31 अगस्त से 16 सितंबर तक 16 दिनों में कुल 68.043 लोगों ने फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। ज़्लेम और ऑज़्जेज़्शन दर्ज कराने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। मुज़्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के 17 सितंबर के आआंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त तक 2,12,400 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके थे। इसके बाद 16 दिनो में 68,043 नए आवेदन आए है।

विविध समाचार

बीएसईबी २९ जिलों में ३३०.०७ करोड़ की लागत से बनाएगा हाईटेक परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह

पटना १९/०९ (संवाददाता): बिहार में विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा सुविधा उपलज़्ध कराने, विद्यालयों में पठन-पाठन को निर्बाध बनाए रखने तथा परीक्षा एवं अन्य संवेदनशील प्रशासनिक कार्यों के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में माननीय मुज़्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के अनुरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 29 जिलों में 29 बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 330 करोड़ 7 लाख 13 हजार 343 रुपये (330.07 करोड़) की लागत आएगी। सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे अब निर्माण की सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं। इस संबंध में बिहार के विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, ने बताया कि 27 जिलों में 29 स्थानों पर चार मंजिला परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा भवन के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ0 त्यागराजन एस0 एम0 के नेतृत्व में समिति द्वारा परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में यह आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग तथा अन्य विभागों/आयोगों द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न परीक्षाएं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं। ऐसे में समर्पित परीक्षा भवन उपलज़्ध होने से परीक्षा आयोजन के लिए शिक्षण संस्थानों पर निर्भरता कम होगी। हाल के परीक्षा आयोजनों के दौरान यह भी देखा गया है कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई होती है और इसमें अतिरिक्त समय लगता है। जिला मुज़्यालय के प्रमुख संस्थानों में परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह के निर्माण से इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित परीक्षा भवनों में एक साथ लगभग 4,000 परीक्षार्थी CCTV की निगरानी में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के बाद इन भवनों में उज़रपुस्तिकाओं का भंडारण किया जा सकेगा तथा इन्हें मूल्यांकन केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आवश्यकता के अनुसार उज़रपुस्तिकाओं की बारकोडिंग एवं स्कैनिंग की सुविधा भी

उपलज़्ध कराई जा सकेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 09 प्रमंडलीय मुज़्य जिलों में पूर्व में परीक्षा भवन-सह-क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है। इनका उपयोग ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, गैर-आवासीय नि:शुल्क कोचिंग तथा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। अब शेष 29 जिलों में 29 परीक्षा भवन-सह-वज्रगृहों के निर्माण से राज्य में परीक्षा आयोजन के लिए समर्पित आधारभूत संरचना का और विस्तार होगा। यह पहल विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलज़्ध कराने, विद्यालयों में पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने तथा परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए आधुनिक और बहुउद्देशीय आधारभूत संरचना उपलज़्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पटना में स्थापित बापू परीक्षा परिसर बिहार में बड़े पैमाने पर परीक्षाओं के आयोजन के लिए विकसित आधुनिक परीक्षा आधारभूत संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है। कुज़्हरार स्थित इस परीक्षा परिसर का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया गया था। पांच मंजिला इस परिसर को एक साथ बड़ी संज़्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। बापू परीक्षा परिसर में एक साथ 16,600 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा व्यवस्था की क्षमता है, जबकि लगभग 3,500 अज़्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। परिसर में परीक्षा संचालन के लिए बड़े परीक्षा हॉल के साथ CCTV आधारित निगरानी, नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलज़्ध कराई गई हैं।बापू परीक्षा परिसर की तर्ज पर अब जिला स्तर पर प्रस्तावित 29 हाईटेक परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह विकसित किए जा रहे हैं। इन भवनों में एक साथ लगभग 4,000 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की सुविधा के साथ उज़रपुस्तिकाओं के सुरक्षित भंडारण, मूल्यांकन केंद्र, 24म7 ष्टष्टञ्जङ्क निगरानी, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलज़्ध होंगी। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा आयोजन के लिए आधुनिक एवं समर्पित आधारभूत संरचना का विस्तार होगा। इन 29 स्थानों पर बनने वाले वज्रगृह में परीक्षाओं के लिए आवश्यक गोपनीय सामग्री का सुरक्षित भंडारण किया जा सकेगा। आवश्यकता के अनुसार निर्वाचन कार्यों से संबंधित संवेदनशील सामग्री का भंडारण भी यहां किया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ शिक्षण संस्थानों को मिलेगा। निर्वाचन जैसे कार्यों के दौरान विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों का उपयोग कम होने से वहां पठन-पाठन को लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में होने वाला व्यवधान कम किया जा सकेगा। इन हाईटेक बहुउद्देशीय भवनों में फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं रहेंगी। साथ ही 24म7 ष्टष्टञ्जङ्क के माध्यम से निगरानी एवं रिकॉर्डिंग की व्यवस्था उपलज़्ध होगी। जिस विद्यालय या महाविद्यालय में परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह का निर्माण किया जाएगा, उसे संचालन के लिए भवन सौंपा जाएगा। संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार इन भवनों में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां एवं आंतरिक परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे। इस प्रकार ये भवन केवल परीक्षा आयोजन के लिए ही नहीं, बल्कि संबंधित शिक्षण संस्थानों के लिए भी उपयोगी बहुउद्देशीय सुविधा के रूप में काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग के फैसले को बताया काला दिन, जानें ज़्या है नया नाम और चुनाव चिह्न

कोलकाता १९/०९ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की पूर्व मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत 6 अज़्टूबर को नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस का नाम और उसका पारंपरिक फूल और घास वाला चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया गया था। आपसी झगड़े के बीच, ममता और रिताब्रता बनर्जी के गुटों ने ञ्जरूष्ट के पारंपरिक फूल और घास वाले चुनाव चिह्न पर अपना दावा जताया था।

हालांकि, चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को इसके इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने ममता के गुट को फ़ुटबॉल खिलाड़ी का चुनाव चिह्न दिया है और उसका नाम %ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा है, जबकि विरोधी गुट को लिफ़ाफ़ा चुनाव चिह्न और डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम मिला है।तीन बार मुज़्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री रह चुकीं ममता ने चुनाव आयोग के फ़ैसले की आलोचना की है और इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बताया है। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने और लोकतांत्रिक व क़ानूनी तरीकों से ञ्जरूष्ट की असली पहचान और फूल-घास वाला चुनाव चिह्न वापस पाने का संकल्प लिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनके गुट को समर्थन दिया है। कोलकाता में एक मीडिया ब्रीफ़िंग में ममता ने कहा, एक माँ बच्चे को खोने का दर्द समझती है, और बच्चा माँ को खोने का दर्द समझता है।

जिन्होंने संघर्ष करके यह संगठन नहीं बनाया, वे उस भावनात्मक जुड़ाव को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा, मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ सकती। यह वह पार्टी है जिसे मैंने 29 वर्षों के संघर्ष, त्याग और राजनीतिक लड़ाइयों के ज़रिए बनाया है। जब तक मैं जीवित हूँ, यह पार्टी मेरे साथ रहेगी और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी।

हालांकि, बागी गुट ने चुनाव आयोग के फ़ैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे इस अंतरिम व्यवस्था का पालन करेंगे। बागी गुट के विधायक अखरुज़्ज़मान अंसारी ने गुरुवार को कहा, हम श्वष्ट के आदेश को मानते हैं। ज़ाहिर है, हम घास पर दो फूल वाला चुनाव चिह्न चाहते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी के लिए एक अंतरिम आदेश दिया है। हमें भरोसा है कि जब आयोग अपना अंतिम फ़ैसला सुनाएगा, तो हमें पार्टी का आधिकारिक और असली नाम और चुनाव चिह्न मिल जाएगा।

उज़र प्रदेश में अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, योगी आदित्यनाथ का ऐलान

लखनऊ १९/०९ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अगले छह महीने में राज्य में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुज़्यमंत्री ने यहां उज़र प्रदेश लोक सेवा आयोग (उप्रपीएससी) और उज़र प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उप्रएसएससी) द्वारा विभिन्न विभागों के पदों पर चयनित 818 अज़्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पिछली समाजवादी पार्टी सरकार (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा, 2017 से पहले जिन लोगों ने नियुक्ति पत्रों के वितरण में गड़बड़ी की थी, उनसे कहना चाहता हूं कि नोट कर लें, आज से फिर नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले छह महीने के अंदर एक लाख से अधिक युवाओं को उज़र प्रदेश में सरकारी नौकरी देंगे। नौकरियां

वे (विपक्ष) गिनती करें, हम (नौकरी) देते जाएंगे। मुज़्यमंत्री ने 2017 से पहले राज्य की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, उस समय उज़र प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ज़्या थी, हर दूसरे दिन दंगा होता था, महीनों-महीनों तक कर्फ़्यू रहता था और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने भर्ती बोर्डों और आयोगों में अपने रिश्तेदारों को बैठाकर पूरी प्रक्रिया को बदनाम कर दिया था। योगी ने कहा, तब एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं होती थी। युवा पलायन करता था। उसके सामने एक ओर कुआं था और दूसरी ओर खाई, ज़्योंकि उज़र प्रदेश में नौकरी नहीं थी और राज्य के बाहर उसके सामने पहचान का संकट था। मुज़्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत चयनित अज़्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड और आयोग अब सरकार की राजनीति का शिकार नहीं होते हैं तथा रीक्षाओं की प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पूरी होती है, जिसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र 'दयालु', संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया।

दिल्ली, लद्दाख और अंडमान के उपराज्यपालों ने पमं मोदी से की मुलाकात

नयी दिल्ली १९/०९ (संवाददाता): शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब तीन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों (रुत्र) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर अलग-अलग मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सज़्सेना और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृज़्) शामिल रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।'' पीएमओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ''लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सज़्सेना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।'' पीएमओ ने एक और पोस्ट में कहा, ''अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृज़्) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।''राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उपराज्यपालों की प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा साझा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे, लद्दाख में विकास कार्यों और अंडमान-निकोबार में सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा हुई होगी।

अधिकारी के आत्महत्या में नाम आने पर पंजाबके मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा

चंडीगढ़ १९/०९ (संवाददाता): अमृतसर स्थित पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में नाम सामने आने के बाद पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने शनिवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से बताया कि तरनतारन के पट्टी से विधायक भुल्लर को मुज़्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर इस्तीफा देने को कहा गया था। मान ने भुल्लर का मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगा और स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुज़्य सचिव केएपी सिन्हा को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। मान ने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा दिया गया है और उन्होंने दोहराया कि सरकार लापरवाही या उत्पीड़न के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखती है। उन्होंने मुज़्य सचिव को अधिकारी की मृत्यु के कारणों की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटनाक्रम अमृतसर स्थित पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक

गगनदीप सिंह रंधावा की कथित तौर पर विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की घटना के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और उन्होंने भुल्लर का नाम लिया है।

विपक्षी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि रंधावा ने सेल्फोस नामक जहर का सेवन करके आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि रंधावा को कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया गया था। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने ङ्ग पर लिखा कि (उन्होंने) मंत्री के सहायक को निविदा देने के लिए दबाव डाले जाने का दावा किया, और कहा कि उन्होंने इसके बजाय एक वैध बोलीदाता को चुना। मजीठिया ने आगे कहा कि (उन्होंने) आरोप लगाया कि उन्हें मंत्री के घर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। भुल्लर ने इन आरोपों को बिल्कुल निराधार और झूठा बताया। तरन तारन के पट्टी से विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि हमारी पार्टी हमेशा सत्य का समर्थन करती है और सत्य के साथ खड़ी रहती है।

एग्जाम स्पेशल ट्रेन में देरी पर भड़के छात्र, स्टेशन पर की तोड़फोड़

पटना १९/०९ (संवाददाता): पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात छात्रों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल, बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों छात्र ट्रेनों की कमी और उनके लेट होने से नाराज थे। देखते ही देखते यह गुस्सा हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। गुस्साए छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेनों को रोक दिया, पथराव किया और एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू-गैस के गोले छोड़ने पड़े। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा दो शिफ़्टों में होनी थी, जिसके लिए हजारों छात्र रात में ही स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेनें न होने और गाड़ियों के लेट होने की वजह से छात्रों को डर सताने लगा कि कहीं उनका एग्जाम न छूट जाए। इसी बीच जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पहुंची, तो छात्रों में अफरातफरी मच गई। नाराज छात्र ट्रेन के आगे पटरी पर लेट गए और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।इस हंगामे की वजह से पाटलिपुत्र स्टेशन से गुजरने वाली कई जरूरी ट्रेनों का सफर रुक गया। राजधानी एज़्सप्रेस समेत कई बड़ी ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा।

घटना की खबर मिलते ही रेल आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस दौरान हुए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू-गैस के गोले छोड़े गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खुद रेल आईजी ने हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस बल का नेतृत्व किया।

विविध समाचार

सलाह

अच्छी बॉडी के लिए जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक भारी एक्सरसाइज है। जिसकी शुरुआत करने से पहले वेट लिफ्टिंग के कुछ नियम जान लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे इसका कोई दुष्परिणाम न हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पहले पूरी तैयारी जरूरी है, कम से कम शुरुआती दौर में हफ्ते में एक से तीन दिन मांसपेशियों की एक्सरसाइज जरूर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे आसान विकल्प वेट मशीन से एक्सरसाइज और डंबल करना होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मदद से पेट सहित पूरे शरीर के फैट को कम कर मसल्स को मजबूत बनाया जा सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि इसका इस्तेमाल वजन बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान बढ़ने वाला वजन आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं। लंबे समय तक फिट रहने के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कैसे बढ़ता है वजन

मांसपेशियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के दौरान मसल्स फाइबर में छोटे टीयर्स बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियों में अतिरिक्त कोशिकायें जुड़ती हैं जो भविष्य में फायदेमंद साबित होती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान समुचित आराम और पोषण आपकी मांसपेशियों के निर्माण में मदद करती है जिससे इसकी क्षमता में बढ़ोत्तरी होता है। मांसपेशियों का वजन लोगों में यह भ्रम होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों का वजन बढ़ना शरीर में अतिरिक्त चर्बी के बढ़ने के बराबर होता है। जबकि यह सच नहीं है, इसके विपरीत यदि मांसपेशियों का एक पाउंड वसा के एक पाउंड से काम जगह लेता है। इस दौरान आपके शरीर का आकार और वजन दोनों बढ़ेगा।

कैसे करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

शुरूआत में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेनर की देखरेख में ही करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में जहां फायदा है वहीं खतरा भी है। क्यों कि इससे आपकी मसल्स खिंच सकती हैं और चोट भी लग सकती है। अगर चोट से बचना है तो आप पहले ठीक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना सीखें। इसमें सभी मसल्स ग्रुप की अपनी अहमियत है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है, जिनके घुटनों में अर्थराइटिस है।

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है

इसके लिए सबसे ज्यादा आसान विकल्प वेट मशीन से एक्सरसाइज और डंबल उठाने होते हैं। मशीन से आपको सही मूवमेंट सीखने को मिलती है। आपको सही मूवमेंट सीखने को मिलती है। मशीन को आप अपने कद के हिसाब से ही एडजस्ट करें। अगर मशीन को ठीक से एडजस्ट न किया गया हो। तो आप गलत मूवमेंट में कसरत करेंगे, इससे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं तो आपकी कमर पर बुरा असर पड़ सकता है। शरीर के सभी हिस्से के लिए अलग-अलग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस मशीन, पुश अप्स, पेक डेक मशीन आदि। बैक के लिए सीटेड रो मशीन, बैक एक्सटेंशन, पुलडाउन। बाइसेप्स के लिए बाइसेप्स कर्ल, हैमर्स, कानसेन्ट्रेशन कर्ल। ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, डिप्स, किकबैक्स। पेट के लिए क्रंच, रीवर्स क्रंच, ऑब्लिक ट्विस्ट, पेल्विक टिल्ट आदि होते हैं।

बढ़ते बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व

बच्चों को बड़ों के मुकाबले खाने में पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा होती है। यह उनके बढ़ने की उम्र होती हैं, इस समय उनका शारीरिक विकास हो रहा होता है। बच्चे सारा दिन वे उछलकूद मचाते रहते हैं। इसलिए उनके उचित विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की दरकार होती है। पोषक तत्व बच्चों को कुछ बीमारियों, जैसे- मोटापा और हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में सहायता करते हैं। इससे बच्चा पूरी क्षमता के साथ विकास करता है। एक बढ़ते हुए बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ-साथ बीच में स्नैक्स की जरूरत होती है।

आवश्यक पोषक तत्व

» **प्रोटीन**- प्रोटीन शरीर के उतकों को बनाने, रख-रखाव और मरम्मत करने में सहायता करता है। प्रोटीन की ज्यादा मात्रा दूध और डेयरी प्रोडक्ट, दालें, अंडे, मछली और मांस में होती है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता विशेषकर तेजी से बढ़ रहे बच्चों को होती है। रोजना अपने बच्चे को प्रोटीन से भरपूर पदार्थ खिलाएं।

» **विटामिन और खनिज**- विटामिन और खनिज शरीर को स्वस्थ बनाता है, साथ ही शरीर के विकास में सहायता करता है। बच्चों के लिए आयरन और कैल्शियम बहुत आवश्यक है। बढ़ रहे बच्चे को अपनी हड्डियां और दांत मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरुरत होती है। दूध, दूध से बने पदार्थ और हरी पतेदार सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्त्रोत है। किशोर अवस्था में बच्चों की कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति केवल खाने से ही पूरी नहीं होती, बल्कि कुछ अतिरिक्त कैल्शियम सप्लिमेंट की जरुरत भी होती है।

» **कार्बोहाइड्रेट और वसा**- बच्चों में शारीरिक विकास के लिए जिस ऊर्जा और कैलोरी की जरुरत होती है उसकी पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चे तेजी से विकास करते हैं, जिससे उनको भूख ज्यादा लगती है।

» **आयरन**- आयरन खून बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। आयरन खून बनाने के अलावा ध्यान और एकाग्रता को सुधारने में सहायता करता है। मांस, अंडा, मछली, हरी पतेदार सब्जियां, आयरन के अच्छे स्त्रोत हैं। जब विटामिन सी से भरपूर भोजन हम करते हैं तो उस शाकाहारी खाने में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है।

» **फल और सब्जियां**- फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन और खनिज स्वस्थ त्वचा, अच्छी ग्रोथ, विकास और संक्रमण से लड़ने के लिए आवश्यक है। सब्जियों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसमें विटामिन ए और सी और सूक्ष्म पोषक जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो बच्चों के शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। साथ ही बड़ी उम्र में कैंसर और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। साबुत अनाज, मांस और डेयरी प्रोडेक्टस में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। फलों में भी फाइबर की मात्रा, विटामिन ए और सी और पोटेशियम होता है। सब्जियों की तरह फलों में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है।

» **अनाज**- आप जितना अनाज खाते हैं, उसमें कम से कम आधा अनाज दलिया, आटा, मक्का, ब्राउन चावल और गेहूं की रोटियां होनी चाहिए। बेहतर होगा कि केवल एरोबिक्स करने के बजाय इसको अलग-अलग एक्सरसाइज के कॉबिनेशन में करें। बहुत हेवी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज वजन घटाने का सही तरीका नहीं हैं। इनकी मदद से आप मसल्स बना सकते हैं, शरीर को मजबूत कर सकते हैं लेकिन ज्यादा वजन नहीं घटा सकते। बेहतर तरीका है कि आप कार्डियो एक्सरसाइज के साथ इनका कॉबिनेशन बनाएं।

उपरोक्त टिप्स अपनाकर आप भी अपने शरीर से फैट को कम कर सकते हैं, साथ ही आप फिट रहेंगे।

सुझाव

फैट बर्निंग टिप्स बढ़ाएं आपकी फिटनेस

शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्बी न सिर्फ आपकी सुंदरता को कम करती है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर डालती है। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। क्या आप भी मोटापे के कारण बीमारियों के खतरों से घिरे रहना चहते हैं या फिर कुछ फैट बर्निंग टिप्स की मदद से अपनी चर्बी कम करके फिट शरीर पाना चाहेंगे। कुछ लोगों की पहली पसंद फिट रहना होती है। वहीं कुछ लोग एक्सरसाइज करने या शरीर की चर्बी कम करने को प्राथमिकता नहीं देते। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके शरीर पर चर्बी कम रहती है और उनका वजन भी संतुलित रहता है। ऐसे लोग बीमारियों से दूर रहने के साथ ही स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहते हैं। इस लेख के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह आप भी आसान फैट बर्निंग टिप्स की मदद से स्लिम और आकर्षक लग सकते हैं। हजार पुशअप्स या क्रंचेज मार लेने या कड़ी मेहनत वाली एक्सरसाइज करने से ही आपकी चर्बी कम नहीं होती। चर्बी कम करने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको भोजन व एक्सरसाइज का चुनाव सोचसमझकर करना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज करें, जिससे शरीर के सभी हिस्सों की मांसपेशियों में गतिविधि हो। पेट की चर्बी कम करने के लिए कार्डियोवस्कुलर एक्सरसाइज फायदेमंद रहती हैं।

खाने का रखें खास खयाल

खाने में गेहूं की बजाय जौ और चने के आटे की रोटी का सेवन करें। जौ और चने के सेवन से आप अतिरिक्त कॉर्बोहाइड्रेट लेने से बचेंगे। इससे आपके शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा नहीं होगी। नारियल चटनी का सेवन करें, यह शरीर को स्फूर्ति देता है और इसमें कैलोरी कम होती है। शक्कर कम मात्रा में लें, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा से मात्रा में लें। विटामिन सी युक्त आहार लें, इससे शरीर में कोर्टिसोल नियंत्रित रहेगा। विटामिन सी वाले पदार्थों में कार्निटाइन नामक तत्व होता है जो शरीर की अतिरिक्त फैट को बर्न करता है। संतरे, शिमला मिर्च, टमाटर और नींबू आदि साइट्रस फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अपने खाने में हरी सब्जियों, मेवे और लीन मीट को शामिल कीजिये।

फायदेमंद एक्सरसाइज

कार्डियो वर्कआउट्स फैट घटाने के लिए बेहतर विकल्प हैं। 500 क्रंच करने की बजाय ऐसे व्यायाम करें जिनसे ज्यादा मात्रा में फैट बर्न होता है। विंडमिल, टर्किश सिटअप्स और रस्सी कूदना आदि करें। एरोबिक एक्सरसाइज भी खुद को फिट रखने का बेहतर विकल्प है। हालांकि एरोबिक्स से वजन पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल है। इससे शरीर लचीला और मजबूत बनता है। जिम जाने के साथ ही दिनभर में ऐसे काम भी कीजिये जिससे आप एक्टिव रहें। आप चाहे तो शाम के समय पार्क में जाकर दोस्तों या छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं।

नेचुरल माउथ फ्रेशनर से इस तरह रखें बच्चों का ख्याल

जिस तरह बड़ों को मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए माउथ फ्रेशनर की जरुरत पड़ती है, उसी तरह बच्चों को भी इसकी जरुरत होती है। पर आप उन्हें ऐसा माउथ फ्रेशनर देना चाहते हैं जो उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। बाजार से मिलने माउथ फ्रेशनर में इस तरह के तत्व होते है जो बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। इसके कारण बच्चों को मुंह से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे में आप घर पर बने माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते है। इसका स्वाद कड़वा न होने के कारण बच्चे इसे आराम से खूस कर लेंगे।

1. अनार का छिलका

अनार का छिलका एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल के गुणों से भरपूर होता है। इस माउथ फ्रेशनर को बनाने के लिए अनार के छिलके निकाल कर धूप में अच्छी तरह सुखा लें। सुखने के बाद इसका पाउडर बना कर पानी में दो चम्मच उबाल लें। उबालने के बाद इसे ठंडा होने पर इसे छान कर दें। इसका स्वाद मिठा होने के कारण बच्चें इसका इस्तेमाल आराम से कर लेंगे।

2. अदरक

बच्चों की मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर है। अदरक को कद्दूकस करके इसमें नमक और काली मिर्च को मिलाएं। इस मिश्रण को कम से कम तीन-चार दिनों तक सुखाएं। सुखने के बाद इसके डिब्बे में रख लें। इस माफथ फ्रेशनर से मुंह के दुर्गंध के अलावा मुंह के किटाणु भी दूर हो जाते है।

3. पुदीना

पुदीने से तो कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा माफथ फ्रेशनर भी है। पुदीने के पत्तों को धूप में अच्छी तरह सुखा कर पीस लें। खाना खाने के बाद बच्चों को खुशी करवाएं। अगर बच्चे इसे करने से मना करते है तो आप उन्हें ये ऐसे भी दें सकते है।

4. सौंफ

अगर बच्चें इन माफथ फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उन्हें सौंफ से बना माउथ फ्रेशनर भी करवा सकते है। इसके लिए सौंफ में हरा धनिया, आधा कप तिल और आधा कप इलायची कर अच्छी तरह भूनने के बाद पीस लें। इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दें इससे बच्चों को ये टेस्टी लगेगा।

शाकाहारियों के लिए डायट प्लान

शाकाहारियों के लिए डायट प्लान में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिये। इसे बनाते समय लिंग आयु और वजन के हिसाब से बनाना चाहिए। शाकाहारियों को हरी पतेदार सब्जियां और फलों का सेवन अधिक करें। प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोयाबीन, टोफू, सोया मिल्क और टोंड अथवा डबल टोंड दूध लें। स्प्राउट्स, दालों आदि का सेवन करें। चपाती बनाने के लिए गेहू के आटे में चना और सोया का आटा मिला लें।

रेसिपी

साबूदाने का चीला

सामग्री

1 कप साबूदाना, 2 बड़े आलू (उबले हुए), 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 2 टे.स्पून बारीक कटा हरा धनिया, 1 टी स्पून जीरा, आधा कप मूंगफली भुनी हुई, 4-5 टी स्पून देसी घी, नमक स्वादानुसार।

विधि

साबूदाने को धोकर उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर का 1 घंटे के लिए ढककर रख दें। भुनी हुई मूंगफली को कूट लें। साबूदाने को एक बाउल में डालकर उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, नमक और कुटी हुई मूंगफली मिला दें। तवा गरम कर उसपर मिश्रण फैला दें। ऊपर से घी भी डाल दें, पलटकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सेंक लें। हरी चटनी के साथ सर्व करें।

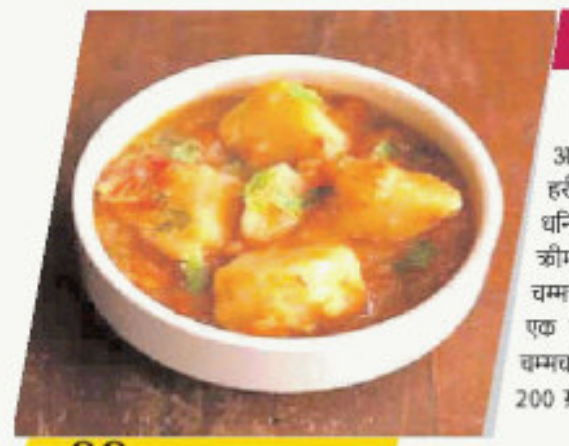

दही आलू टमाटर सब्जी

सामग्री

आलू- एक किलो, टमाटर- 100 ग्राम, हरी मिर्च- पांच, अदरक- डेढ़ इंच, हरी धनिया- डेढ़ बड़े चम्मच, दही- 100 ग्राम, क्रीम- 100 ग्राम, सिंघाड़े का आटा- दो बड़े चम्मच, सेंधा नमक- स्वादानुसार, जीरा- एक बड़ा चम्मच, गरम मसाला- डेढ़ बड़े चम्मच, लाल मिर्च- पांच साबुत, मक्खन- 200 ग्राम

विधि

आलू उबालकर फिर छीलकर इनके डेढ़ इंच चौकोर टुकड़े कर लें। टमाटर महीन काट लें। हरी मिर्च व अदरक काट लें। दही में एक चौथाई टी-कप पानी व सिंघाड़े का आटा मिलाकर फेंट लें। क्रीम छान लें। मक्खन गर्मकर साबुत लाल मिर्च, जीरा व हरी मिर्च का छौंक देकर आलू मिला दें। इसमें गरम मसाला, सेंधा नमक, टमाटर, दही, क्रीम व डेढ़ टी-कप पानी देकर उबाल आने तक करीब पांच मिनट पका लें। हरी धनिया व अदरक देकर उतार लें। स्वादिष्ट व पौष्टिक सब्जी सिंघाड़े के आटे से बनी पूड़ियों के साथ गरमागरम परोसें।

बच्चों को सुसाइड के लिए उकसाता है यह गेम

पेरेंट्स ना बरतें लापरवाही

बच्चों से लेकर बड़ों तक ऐसा कोई नहीं जिसे गेम खेलना पसंद न हो। फ्री टाइम में चाहे घर पर हो या बाहर गेम खेलना बेस्ट टाइम पास माना जाता है। लेकिन देखा गया है कि बच्चे इन गेम्ज के ज्यादा आदी होते हैं। इसलिए, माता-पिता को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चे किसी ऐसे रास्ते पर न चले जाएं, जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। वर्किंग पेरेंट्स के लिए यह बात ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सारा दिन वह अपने बच्चे के साथ नहीं होते। ऐसे में उनका बच्चा क्या कर रहा है, इस बात की खबर उन्हें होनी चाहिए।

भारत में पहुंची दहशत

कुछ समय पहले पोकेमॉन नाम की एक गेम काफी फेमस हुई थी, जिसने बड़ों से लेकर बच्चों तक पर अपना गहरा असर दिखाया था। सोते, उठते, जागते अधिकतर लोग इसी गेम को खेलने के आदी हो चुके थे। लेकिन अब एक ऐसी गेम चर्चा में है, जो बच्चों को सुसाइड के लिए उकसाती है। ब्लू व्हेल नाम की यह गेम अब तक दुनियाभर में करीब 250 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुकी है। इसे 25 साल के फिलिप बुडेकिन ने साल 2013 में बनाया था। अब इस गेम की दहशत भारत में भी पहुंच चुकी है।

गेम से बाहर निकलना मुश्किल

यह गेम क्लोज्ड ग्रुप में खेला जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे साइट्स पर इंविटेशन के जरिए बच्चे इस गेम में शामिल होते हैं। इसमें 50 स्टेज को 50 दिनों में पूरा करना होता है। हर स्टेज पर प्लेयर को खुद को तकलीफ देते हुए एक तस्वीर ग्रुप पर भेजनी पड़ती है। गेम को सबसे खतरनाक बात यह है कि जब भी बच्चे इस गेम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो गेम चलाने वाले आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते है। पुलिस की मानें तो माता-पिता को अपने बच्चों की तरफ खास ध्यान देना होगा, ताकि उन्हें इस खतरनाक गेम से बचाया जा सके।

कलिंग समाचार

संपादकीय

संसद में गतिरोध और सुविधा का लोकतंत्र

संसद के मानसून सत्र में अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हुआ हो। बल्कि अजीब नजारा देखने मिला जब एनडीए के सांसदों ने भी संसद परिसर में खड़े होकर हंगामा किया और राहुल गांधी से जवाब मांगा। राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे, इस पर सवाल उठाया। दरअसल जंतर-मंतर पर हुए सफल छात्र आंदोलन के बाद से सरकार लगातार अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो रही है। पहले तो नरेन्द्र मोदी को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। इस बीच झारखंड में भी परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो चुका है, तो भाजपा और उसके साथी दल यहां राहुल गांधी को घेर रहे हैं, उनसे झारखंड पर जवाब मांग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर साफ कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जो कार्रवाई की वह ठीक नहीं है और वे भी इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बाकायदा आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात भी की थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर भाजपा राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती, कांग्रेस पार्टी को राजनीति में अप्रासंगिक मानती है, तो फिर उसके सांसद यह मांग क्यों कर रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड जाएं। वे यही मांग प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं करते। अगर वे ऐसा मानते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है, और इस नाते राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। तो इस तर्क के हिसाब से तो जंतर-मंतर पर पहले दिन ही नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और धर्मेन्द्र प्रधान को आना चाहिए था। असल में भाजपा भी जानती है कि उसका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, समाधान देना नहीं। इसलिए न जंतर-मंतर न झारखंड मोदी-शाह कहीं नजर नहीं आए और सारा ठीकरा अब राहुल गांधी पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा के इस पैंतरे का उल्टा असर हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा सांसदों को भी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राहुल गांधी से उ मीद है कि छात्रों का हित वही सोचेंगे। लेकिन इस समय चिंता इस बात की भी करना चाहिए कि किस तरह पूरा मानसून सत्र लगभग बेकार चला गया क्योंकि अमित शाह और नरेन्द्र मोदी सदन में आने से बचते रहे। मोदी सरकार का दावा है कि विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए छात्र प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा कराने और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब दिलाने की पेशकश की गई। लेकिन कांग्रेस इसे पर्याप्त नहीं मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर केवल सामान्य चर्चा या गृह मंत्री का भाषण पर्याप्त नहीं है। पार्टी की स्पष्ट तौर पर तीन मांगें हैं- पहली मांग छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से साफ़ जवाब की है। दूसरी मांग छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की है। तीसरी मांग अयोध्या के राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब की है। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में राहुल गांधी ने एक लेख लिखकर इन मांगों को दोहराया था, फिर सोमवार शाम ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर फिर से इन्हीं बातों को कहा था। इसके अलावा वे जिस मंच पर जाते हैं, वहां यही सवाल अमित शाह के सामने रखते हैं कि क्या आपने कील लगी लाठियां और पैलेट गन चलाने के आदेश दिए और अगर आपने नहीं दिए तो फिर गृह मंत्रालय से किसने ऐसा करने कहा। इतने ज्यादा सरल और स्पष्ट शब्दों में ये सवाल पूछे गए हैं, फिर भी अमित शाह सीधा जवाब देने की जगह अब भी इस मुद्दे पर चर्चा की बात कह रहे हैं। उनका यह रवैया नरेन्द्र मोदी की तरह ही है, जिनसे अमेरिका में सवाल गौतम अडानी के साथ संबंधों को लेकर हुआ था और उन्होंने जवाब दिया था कि भारत लोकतंत्र की जननी है। बहरहाल, मोदी-शाह के बचाव में उतरे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं के आंदोलनों तथा उनके खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का सरकार की ओर से जवाब देंगे और हर मुद्दे पर बिंदुवार प्रतिक्रिया देंगे।

मक्का समझौता-बदलता शक्ति-संतुलन और भारत की चुनौती

मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग

कानूनी फ़ॉर्म नई परिस्थितियों में भारत को यही बढ़त बनाए रखनी होगी—शोर से नहीं, शक्ति और रणनीति से। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम इस नए गठबंधन से उपजी नई सामरिक और आर्थिक चुनौतियां का सामना करने के लिए देश में अमन और प्रेम को बनाएं रखें, फसादी फिरकापरस्त ताकतों का समूल उन्मूलन करें ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र दूरदर्शी निर्णय लिए जा सकें। मक्का में 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ संयुक्त रक्षा समझौता महज तीन देशों के बीच सैन्य सहयोग का ही दस्तावेज नहीं है बल्कि पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण और मध्य एशिया तक उभरती नई सामरिक तस्वीर का संकेत भी है। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। यह व्यवस्था गत वर्ष 17 सितंबर 2025 के पाकिस्तान-सऊदी स्ट्रेटेजिक यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को एक नए, त्रिपक्षीय आयाम में ले जाती है।

इस गठजोड़ की असली ताकत तीनों देशों की अलग-अलग क्षमताओं के मेल में है। सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन और ऊर्जा-स पदा है। विश्व बैंक के अनुसार 2025 में उसकी नॉमिनल जीडीपी करीब 1.28 ट्रिलियन डॉलर रही। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसकी सैन्य क्षमता में निवेश की क्षमता। एसआईपीआरआई के अनुसार 2025 में सऊदी अरब ने रक्षा पर लगभग 83.2 अरब डॉलर खर्च किए और वह दुनिया का आठवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा।

तुर्किये इस गठजोड़ को सैन्य तकनीक, रक्षा उद्योग और युद्ध-अनुभव देता है। 2025 में उसका सैन्य व्यय करीब 30 अरब डॉलर था। ड्रोन, मिसाइल, ब तरबंद वाहन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में तुर्किये ने उल्लेखनीय क्षमता विकसित की है। उसका मध्य एशिया में बढ़ता राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी इस समीकरण को केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहने देता। तुर्किये लंबे समय से तुर्क भाषी मध्य एशियाई देशों के साथ परिवहन और व्यापार गलियारों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध॰द्यह्यश्र ऋद्धडुस्र - छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया तीसरा और सबसे संवेदनशील स्तंभ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता सऊदी अरब और तुर्किये की तुलना में बहुत छोटी है—2025 में उसका सैन्य खर्च लगभग 11.9 अरब डॉलर था—लेकिन उसके पास परमाणु हथियार और बड़ा, युद्ध-अनुभवी सैन्य ढांचा है। स्वतंत्र विशेषज्ञ आकलन पाकिस्तान के परमाणु भंडार को लगभग 170 वारहेड मानते हैं। ज़्यादा जानें एशियाई और प्रवासी दक्षिण-एशियाई और प्रवासी शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका यानी समीकरण मोटे तौर पर ऐसा है—सऊदी अरब-पैसा और ऊर्जा, तुर्किये-रक्षा तकनीक और सैन्य औद्योगिक क्षमता, जबकि पाकिस्तान-परमाणु क्षमता और सैनिक अनुभव। यही इस गठजोड़ को साधारण द्विपक्षीय समझौते से अलग बनाता है।

लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है—इसका असर कितना गंभीर है? भारत के लिए यह समझौता कोई ख़ास चिंताजनक नहीं है, पर इसे हल्के में लेना भी भूल होगी। पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष केवल सीमित सैन्य विवाद नहीं है। आतंकवाद, सीमा-पार घुसपैठ और कश्मीर सहित अनेक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक तनाव है। ऐसे में यदि पाकिस्तान को सऊदी वित्तीय समर्थन, तुर्की की उन्नत रक्षा तकनीक और एक औपचारिक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था मिलती है तो इस्लामाबाद की सामरिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हो सकती है। विशेष चिंता इस बात की है कि तुर्किये का जुड़ना पाकिस्तान को केवल पश्चिम एशिया की राजनीतिक छतरी नहीं देता, बल्कि भूमध्यसागर, काकेशस और मध्य एशिया तक फैले एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ता है। भविष्य में रक्षा उत्पादन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया साझेदारी और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ा तो इसका प्रभाव दक्षिण एशिया तक पहुंच सकता है। भारत समाचार ज़्यादा जानें अर्थजगत समाचार हिंदी समाचार सदस्यता समाचार पत्र सदस्यता फिर भी इस गठजोड़ को तत्काल %इस्लामिक एनएटीओ% मान लेना अतिशयोक्ति होगी। समझौते में सामूहिक रक्षा की राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक युद्ध की स्थिति में प्रत्येक देश किस स्तर तक सैन्य हस्तक्षेप करेगा, इसकी विस्तृत व्यावहारिक शर्तें अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं। विशेषज्ञ संस्था आईआईएसएस ने भी पाकिस्तान-सऊदी समझौते के विवरण को अस्पष्ट बताते हुए उसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव की संभावना पर जोर दिया था। भारत की रणनीति इसलिए प्रतिक्रिया-प्रधान नहीं, बल्कि बहुस्तरीय और दीर्घकालिक होनी चाहिए। पहला, सऊदी अरब से भारत के गहरे आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सऊदी रणनीतिक संबंध भारत-सऊदी साझेदारी की कीमत पर न बढ़ें। दूसरा, तुर्किये के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने चाहिए। मतभेदों के बावजूद अंकारा को पूरी तरह पाकिस्तान के खेमे में धकेल देना भारत के हित में नहीं होगा। व्यापार, निवेश और बहुपक्षीय मंचों पर संवाद जारी रखना आवश्यक है। तीसरा, मध्य एशिया में भारत को अपनी उपस्थिति कहीं अधिक मजबूत करनी होगी। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ संपर्क, ऊर्जा, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भारत के लिए केवल व्यापारिक परियोजनाएं नहीं, बल्कि सामरिक संपर्क के साधन भी हैं। राजनीति विज्ञान चौथा, भारत को अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति पर और तेजी से काम करना होगा। एसआईपीआरआई के अनुसार 2025 में भारत का सैन्य व्यय 92.1 अरब डॉलर था—सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान के संयुक्त खर्च से अधिक। इसलिए चुनौती संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि संसाधनों के अधिक प्रभावी और तकनीकी उपयोग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत को इस नए गठजोड़ को किसी धार्मिक ध्रुवीकरण के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु से अधिक स्थायी होते हैं—राष्ट्रीय हित। मक्का समझौता यदि नई सामरिक धुरी का आरंभ है तो भारत के लिए उसका उत्तर किसी जल्दबाजी या उत्तेजना में नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक पहुंच और क्षेत्रीय साझेदारियों को एक साथ मजबूत करने में है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह आज केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और हिंद-प्रशांत—तीनों को जोड़ने वाली एक उभरती वैश्विक शक्ति है। नई परिस्थितियों में भारत को यही बढ़त बनाए रखनी होगी—शोर से नहीं, शक्ति और रणनीति से। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम इस नए गठबंधन से उपजी नई सामरिक और आर्थिक चुनौतियां का सामना करने के लिए देश में अमन और प्रेम को बनाएं रखें, फसादी फिरकापरस्त ताकतों का समूल उन्मूलन करें ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र दूरदर्शी निर्णय लिए जा सकें

लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें

राजेंद्र शर्मा

मोदी शाही दिमागी नक्सलियों का हौआ खड़ा करने का सहारा ले रही है, तो इसलिए कि उसे जेन ज़ी के हाल के उभार ने डरा दिया और उसे इस अप्रत्याशित हमले की कोई नयी काट सूझ ही नहीं रही है, जबकि हिंदू-मुस्लिम करने का पुराना पत्ता, इसके सामने बेकार साबित हो रहा है। इस उ मीद में कि शायद जेन ज़ी रैडीकल विचारों से वैसे ही डरता होगा, जैसे कि नव-उदारीकरण के शुरू होने के बाद बड़ी हुई मिलेनियल्स की पीढ़ी डरती थी। ऐतिहासिक जगहें और इमारतें यह संयोग ही नहीं है कि भारत के अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर, अपने तेरहवें स्वतंत्रता दिवस संबोधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश को और प्रकट तथा खुली तानाशाही की ओर धकेलने के अपने इरादों का ऐलान करने का मौका बनाया है। मोदी के इस आह्वान का कि कथित हथियारी नक्सलों% के खात्मे के बाद, अब दिमागी नक्सलियों%को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा%; एक और एक ही अर्थ है—तानाशाही को आगे बढ़ाना।

दिमागी नक्सली की संज्ञा अटपटी हो सकती है, पर इसका निशाना एकदम स्पष्ट है—सत्ताधारी संघ-भाजपा के आंदोलनात्मक विरोध को ही नहीं, उसके प्रति आलोचनात्मक विचार को ही, जुर्म बना देना! यह सत्ता के विरोधी विचार मात्र को अपराध बना देना है, जिसकी जनतंत्र की किसी भी परिभाषा में गुंजाइश नहीं हो सकती है। नक्सल% के नाम पर किस तरह मौजूदा निजाम की तमाम वास्तविक आलोचनाओं को मोदीशाही निशाने पर रखने जा रही है, इसका संकेत खुद मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में ही मौजूद था।

बेशक, मोदी का खास निशाना इसमें भी यूपीए के दौर पर है, जब यूपीए-1 के दौरान, सरकार को बाहर से समर्थन दे रही वामपंथी पार्टियों के दबाव ने और फिर यूपीए-2 के दौरान, एक हद तक श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित सलाहकार परिषद ने, बाजारवादी नीतियों के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने का, उनकी धार को भोंथरा करने का काम किया था। मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, वनाधिकार आदि, जनता के अधिकारों का विस्तार करने वाले कानून, इसी प्रकार के अंकुश से निकले थे।

जाहिर है कि इजारेदार पूंजी को अपने राज पर ये अंकुश कभी गवारा नहीं थे और इसीलिए ये अंकुश इजारेदार पूंजी के सबसे मुक मल प्रतिनिधि, संघ-भाजपा को भी गवारा नहीं थे। 12 साल में, सत्ता के गलियारों में औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही हैसियतों से जैसे ठूंस-ठूंसकर आरएसएस-सर्टीफाइड लोगों को भरा जा चुका है, जिसमें भांति-भांति के वंचकों को भरा जाना भी शामिल है, उसके बाद जाहिर है कि ऐसे अंकुश लगाने वाले विचारों के वाहक सत्ता के गलियारों में दूर-दूर तक भी नहीं रहे होंगे। इसके बावजूद, मोदी अगर इस तरह के विचार के लोगों और विचारों का हौआ दिखा रहे हैं, तो इसके तीन ही मकसद हो सकते हैं।

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया पहला, जनता के हित के ऐसे तमाम विचारों तथा उसके अधिकारों की ऐसी चिंताओं को एक प्रकार से अपराध ही बनाकर, शासन से जुड़े लोगों के सोच-विचार के लिए वर्जित ही कर देना। संविधान में गारंटीकृत निजी स्वतंत्रताओं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि को सचेत रूप से संकुचित किया है, उससे जनता को अधिकार-संपन्न नागरिकों के बजाए, लाभार्थी बनाकर, कृपाकांक्षी प्रजा में तब्दील करने का छल साफ हो जाता है।

दूसरा मकसद, यह हो सकता है कि संघ-भाजपा की सारी घेरेबंदी के बावजूद, अगर सत्ता के गलियारों के किन्हीं कोने-अंतरों में कुछ ऐसे लोग कॉकरोचों की तरह छुपे रह गए हों, जो मौजूदा नीतियों की चौतरफा विफलता के कारणों को पहचानते हों, तो उनके फिर से मुखर होने और दूसरों को प्रभावित करने के रास्ते पहले से ही बंद कर दिए जाएं। और तीसरा तथा शायद बाकी दोनों मकसदों से बड़ा मकसद, यह लगता है कि मौजूदा चौतरफा संकट के बीच, जब अब तक अपनी पांचों उंगली घी में होने के बावजूद, इजारेदार पूंजी को अपने दूरगामी लक्ष्यों को लेकर चिंताएं होने लगी हैं, इजारेदार पूंजी को इसका भरोसा दिलाया जाए कि संकट के दबाव में भी मोदीशाही, यूपीए के समय जैसे संतुलनों और अंकुशों की ओर लौटने वाली नहीं है।

अपने 13वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो बार-बार सुधारों का वादा किया है, उसका मकसद बड़ी पूंजी को इसी का भरोसा दिलाना है कि मोदी राज में आम जनता की कीमत पर उसके स्वार्थों की सेवा इसी तरह की जाती रहेगी। ज़्यादा जानें समाचार पत्र प्रकाशन शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका डिजिटल समाचार पत्र बेशक, दिमागी नक्सलियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी द्वारा छेड़ी गयी यह मुहिम इस अर्थ में नयी भी नहीं है कि कथित शहरी नक्सलियों के खिलाफ मोदी राज ने एक प्रकार से शुरू से ही मुहिम छेड़ रखी है। इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी आदि को मिसाल बनाकर, शासन के प्रति आलोचनात्मक रुख को बढ़ावा देने वाली मानी जाने वाली उच्च्च शिक्षा संस्थाओं को और आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले सार्वजनिक बुद्धिजीवियों तथा मूलगामी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और दूसरी ओर जनता के हित के मुद्दों पर अभियान चलाने वाले एनजीओज़ को, शासन की दमनकारी ताकत का निशाना बनाया गया।

राजनीति जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ गढ़ा गया भारत तेरे टुकड़े होंगे नारों का केस, नागरिक अधिकार व जनतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों के खिलाफ थोपा गया भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस और सीएए-विरोधी आंदोलन में सक्रिय हुए विशेष रूप से मुस्लिम युवा बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ थोपा गया दिल्ली दंगा वृहत्तर षड्यंत्र केस, जनतांत्रिक आवाजों के खिलाफ मोदी निजाम की लगातार जारी रही मुहिम के कुछ ही उदाहरण हैं। इसके साथ ही विपक्ष को साम, दाम, दंड, भेद, हर तिकड़म से कमजोर करने और संसदीय बहुमत को हथियार बनाकर तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किए जाने को और जोड़ लें तो, व्यावहारिक माने में तानाशाही का ही नक्शा हमारे सामने आ जाता है।

इसके बावजूद, मोदीशाही %दिमागी नक्सलियों का हौआ खड़ा करने का सहारा ले रही है, तो इसलिए कि उसे जेन ज़ी के हाल के उभार ने डरा दिया और उसे इस अप्रत्याशित हमले की कोई नयी काट सूझ ही नहीं रही है, जबकि हिंदू-मुस्लिम करने का पुराना पत्ता, इसके सामने बेकार साबित हो रहा है। इस उ मीद में कि शायद जेन ज़ी रैडीकल विचारों से वैसे ही डरता होगा, जैसे कि नव-उदारीकरण के शुरू होने के बाद बड़ी हुई मिलेनियल्स की पीढ़ी डरती थी,दिमागी नक्सली% कहकर, रैडीकल विचारों से डराकर, इस पीढ़ी को नव-उदारवादी अंधविश्वासों के बाड़े में बंद रखने की और उसके सहारे बहुसं यकवाद के भी दायरे में बांधे रखने की, कोशिश की जा रही है।

इसीलिए, मोदी के भाषण में दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा% को सीधे इससे जोड़ा गया है कि %राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मु यधारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। भारतीय राजनीति लेकिन, मोदी जी के दुर्भाग्य से इस युवा पीढ़ी ने नव-उदारवादी नीतियों की तबाही से लेकर, राम मंदिर की लूट तक सब देखा है और पूंजी के पश्चिमी गढ़ों में बढ़ती प्रगतिशील विचारों की स्वीकृति से उनका नजदीकी परिचय है। यह पीढ़ी मोदी जी के खड़े किए हौवे से डरकर, मौजूदा निजाम को नियति मानकर स्वीकार करने वाली नहीं है। लाल किले से अपने 76 मिनट के भाषण में मोदी ने 20 बार युवा या युवाओं का इस्तेमाल किया और 16 बार नौजवानों तथा 4 बार नौजवान शब्द का। इसके अलावा उन्होंने 4 बार युवा शक्ति की भी बात की। लेकिन, युवाओं के हाल के आंदोलन, परीक्षा-शिक्षा धांधली को लेकर उनकी चिंताओं का जिक्र करने सचेत रूप से बचते रहे। सारे हाथ-पांव मारने के बाद भी इस मोर्चे पर कुछ हासिल नहीं होगा और यह संकट बढ़ता ही जाएगा, इसका एहसास मोदी को हो गया है। लालकिले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की है कि, %एक बहुत बड़ा वालंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं%, जेन ज़ी तथा जेन अल्फा समेत, जनता के बढ़ते असंतोष तथा आने वाले समय में उठने वाले आंदोलनों से शासन की दमनकारी ताकत के बल पर निपटने की मोदीशाही की तैयारियों का ही हिस्सा है। याद रहे दिल्ली में युवाओं पर दमन में गैर-वर्दीधारियों की सेवाएं खूब ली गयी थीं। नयी सिविल डिफेंस फोर्स, इसी को व्यवस्थित तथा संस्थागत रूप देने का प्रयास लगती है। क्या यह वर्तमान तानाशाही के तेजी से फासीवाद के रास्ते पर बढ़ने का ही मामला नहीं होगा?

विविध समाचार

'झाड़ू–बर्तन सब किया, फिर भी की मारपीट और दर्ज कराए झूठे केस', पत्नी से तंग आकर 28 साल के कारोबारी ने लगाई फांसी

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 28 वर्षीय युवा कारोबारी ने अपनी ही दुकान के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि इस खौफनाक कदम को उठाने से ठीक पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी की प्रताड़ना और उसके जुल्मों को जिम्मेदार ठहराया है। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसने भी युवक का आखिरी भावुक वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। आत्महत्या

करने से पहले युवा कारोबारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने वैवाहिक जीवन का दर्दनाक सच दुनिया के सामने रखा। वीडियो में अपना दर्द बयां करते हुए युवक ने बताया कि वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए घर के सारे छोटे–बड़े काम करता था। उसने कहा, "मैं पत्नी के लिए झाड़ू लगाने से लेकर बर्तन साफ करने तक, घर का हर एक काम करता था।" इसके बावजूद उसे सुखी वैवाहिक जीवन नसीब नहीं हुआ, बल्कि बदले में उसे रोज–रोज के ताने और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। वीडियो में कारोबारी ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घर के सारे काम करने के बाद भी उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। बात सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पत्नी ने उसे फंसाने के लिए उस पर कई झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा दिए थे। पत्नी के इस अमानवीय व्यवहार और झूठे मुकदमों के भारी तनाव ने युवक को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। इसी प्रताड़ना से हार मानकर आखिरकार उसने अपनी ही दुकान में फंदे से लटक कर जान देने का दर्दनाक फैसला ले लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में फंसा चार साल का निर्भय

अंबाला। हरियाणा में अंबाला के धन्यौड़ा गांव में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। महज 4 साल का एक मासूम बच्चा खेलते–खेलते 220 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। इस घटना के बाद से ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें संयुक्त रूप से बेहद कड़ा और संवेदनशील रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पूरे देश की निगाहें इस वक्त मासूम की जिंदगी के लिए चल रही इस जंग पर टिकी हुई हैं। बोरवेल में गिरे इस मासूम बच्चे का नाम निर्भय है। मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की सुबह निर्भय अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे अपने दादा को खाना देने के लिए गया था। खेत में जब बड़े–बुजुर्ग बातचीत और काम में व्यस्त थे, तभी निर्भय वहां पास ही खेलने लगा। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खेत में ही खुले पड़े एक गहरे और खतरनाक बोरवेल में समा गया। बच्चे के गिरते ही चीख–पुकार मच गई और तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सेना और एनडीआरएफ की एक्सपर्ट टीमों को मोर्चे पर उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद फूंक–फूंक कर अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि इस बोरवेल में करीब 60 फीट की गहराई से ही पानी शुरू हो रहा है, जो बच्चे की जान के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। राहत कर्मियों ने रस्सी के सहारे बोरवेल के भीतर स्पेशल अंडरवॉटर कैमरे उतारे हैं ताकि बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस बीच दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने रेस्क्यू टीम की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। मिट्टी धंसने के खतरे को देखते हुए सेना ने तुरंत तत्परता दिखाई और बोरवेल के मुहाने के ऊपर बड़ा टेंट लगाकर ऑपरेशन को बिना रुके जारी रखा। बोरवेल के भीतर की जो स्थिति कैमरों के जरिए सामने आई है, वह बेहद चिंताजनक और भावुक कर देने वाली है।

कांग्रेस ने भाजपा पर अधिकारियों को डराने और कर्मचारियों को निशाना बनाने का लगाया आरोप

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों अनिरुद्ध सिंह और राजेश धरमानी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कर्मचारी और अधिकारी–विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष राजनीतिक दबाव के जरिए सरकारी अधिकारियों को डराने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेताओं के हालिया बयानों पर टिप्पणी करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा का 'कर्मचारी–विरोधी चेहरा' एक बार फिर जनता के सामने आ गया है। मंत्रियों ने कहा कि भाजपा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों की रक्षा करने में लगातार विफल रही है, चाहे वह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का मुद्दा हो या सेवा से जुड़े अन्य मामले।

पंजाब में मां ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंककर दी दर्दनाक मौत, खुद भी सुसाइड करने कूदी

रोपड। पंजाब के रोपड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मोहाली निवासी एक मां ने अपने तीन मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया। घटना के बाद महिला ने भी नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वह तैरकर किनारे आ गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक दो बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। आरोपी महिला की पहचान शकुंतला उर्फ सुमन के रूप में हुई है, जो मोहाली के मटौर इलाके की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने 10 वर्षीय तपिश, 7 वर्षीय तनवी और 4 वर्षीय नितिन को नहर में फेंक दिया। शुरुआती पूछताछ में महिला ने स्वयं बच्चों को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात तक चले अभियान में दो बच्चों के शव बरामद हुए, जबकि सबसे छोटे बच्चे की तलाश मंगलवार को भी जारी रही। परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम जब वे काम से घर लौटे तो शकुंतला और तीनों बच्चे घर से गायब थे। काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के दौरान महिला के मोबाइल की लोकेशन रोपड़ में मिली, जिसके आधार पर पुलिस नहर के पास पहुंची और उसे वहीं से हिरासत में ले लिया। मृतक बच्चों के दादा रामबाबू ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से शकुंतला का व्यवहार सामान्य नहीं था। उनका कहना है कि वह कई बार बच्चों को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें करती थी और घरेलू विवाद भी लगातार होते रहते थे। हालांकि परिवार को कभी अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। परिवार के अनुसार, करीब दस महीने पहले शकुंतला के पति कमल ने भी आत्महत्या कर ली थी।

शिवराज सिंह चौहान और सीएम सैनी ने हरियाणा एफपीओ मिशन-२०२६ का किया शुभारंभ

चंडीगढ। देशभर में किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए 'खेत बचाओ अभियान' का मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने सभी अतिथियों का समारोह में पहुंचने पर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रेवाड़ी जिला के बावल स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से कृषि के नवीनतम नवाचारों पर आधारित कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा हरियाणा एफ.पी.ओ. मिशन–2026 का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जनभागीदारी आधारित प्रयासों को और अधिक गति देने का संकल्प दोहराया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण उन्नत कृषि और समृद्ध किसान के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं और किसानों की समृद्धि ही भारत की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि को लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीकों और किसानों की सक्रिय भागीदारी से भारत विश्व की अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में और अधिक मजबूत होगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में पूरे देश के सामने एक प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही भावांतर भरपाई योजना, 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा', 'मेरा पानी–मेरी विरासत' जैसी योजनाओं ने किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों को हरियाणा की इन पहलों से सीख लेने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल देश के अन्न भंडार को भरने वाला अग्रणी राज्य ही नहीं, बल्कि कृषि क्रांति का मजबूत केंद्र भी है। कभी भारत को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों की मेहनत के कारण देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान देश के 140 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के युवा सीमाओं पर देश की रक्षा करने और खेलों में भारत का गौरव बढ़ाने में भी अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा वास्तव में खेती, सैनिक परंपरा और खेल प्रतिभाकृतीनों क्षेत्रों में पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे आवश्यकता के अनुसार ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरता लगातार प्रभावित हो रही है, पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी उर्वरता को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'खेत बचाओ अभियान' आज समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब यह जन–जन का अभियान बनकर खेतों तक पहुंचेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि तथा समृद्ध कृषि की नींव मजबूत करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.3 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा कृषि क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, जो प्रदेश के किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत आधारशिला है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि हरियाणा भविष्य में भी देश की अन्न शक्ति के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में आज से 'हरियाणा एफ.पी.ओ. मिशन–2026' का शुभारंभ किया जा रहा है, जो छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों से जुड़े लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) सक्रिय हैं। नए मिशन के माध्यम से इन संगठनों को और अधिक मजबूत बनाते हुए कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जाएगा। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा हरियाणा की कृषि मूल्य श्रृंखला को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता भी बढ़ रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है।'उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक संसाधन भी बचें।' उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाई जाएं, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ धरती और पर्याप्त जल संसाधन भी सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधिकरण और जलवायु अनुकूल कृषि को अपनी कृषि नीति का मूल आधार बनाया है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर रोक लगाने के लिए 'हर खेत स्वस्थ खेत' और 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मिट्टी की जांच करवाकर वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'खेत बचाओ अभियान' को प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक माह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों को टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित करने का जनआंदोलन है। हरियाणा सरकार कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से इस अभियान को गांव–गांव तक पहुंचाकर किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल बचत और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति जागरूक करेगी। श्री राणा ने किसानों से आह्वान किया कि वे मिट्टी की जांच करवाकर वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें तथा आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद के उपयोग से बचें। उन्होंने कहा कि संतुलित खाद का उपयोग न केवल मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि उत्पादन लागत कम करने, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि भूमि को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा के किसान इस अभियान को जनभागीदारी का आंदोलन बनाकर हरियाणा को टिकाऊ और समृद्ध कृषि का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट ने कहा कि 'खेत बचाओ अभियान' का समापन वास्तव में नई शुरुआत है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, रविवार 20 सितंबर 2026

पश्चिमी ओडिशा के शहरों और गांवों में नुआखाई पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया

संबलपुर १९/०९ (संवाददाता): पश्चिमी ओडिशा के शहरों और गांवों में प्रमुख कृषि पर्व नुआखाई पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नई फसल, किसानों की मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने वाले इस त्योहार पर लोगों ने सबसे पहले देवी-देवताओं को नए धान से तैयार चावल का भोग लगाया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने एक साथ बैठकर नई फसल से बने भोजन और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। संबलपुर में नुआखाई उत्सव की शुरुआत क्षेत्र की आराध्य देवी मां समलेश्वरी को नई फसल अर्पित करने के साथ हुई।

निर्धारित शुभ मुहूर्त में मंदिर के पुजारियों ने नए धान से तैयार 'नबान्न' देवी को चढ़ाया। इसके बाद मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मां समलेश्वरी की पूजा-अर्चना की और अपने परिवार, कृषि तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस वर्ष नुआखाई के लिए निर्धारित लग्न सुबह 9 बजकर 40 मिनट से 9 बजकर 54 मिनट के बीच था। तुला लग्न और वृषभ नवांश के दौरान मां समलेश्वरी को नई फसल का भोग अर्पित किया गया। पूजा का शुभ समय पुजारियों और ज्योतिषियों ने पारंपरिक गणना के आधार पर पहले ही तय कर लिया था। इसके लिए ब्रह्मपुरा मंदिर में विशेष बैठक आयोजित की गई थी। मां समलेश्वरी को नबान्न अर्पित किए जाने के बाद पश्चिमी ओडिशा के घरों में पारिवारिक पूजा शुरू हुई। परिवारों ने अपने कुल देवी-देवताओं और ग्राम देवी को नए धान से तैयार चावल, मिठाइयां तथा स्थानीय व्यंजन अर्पित किए। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद सभी सदस्यों ने साथ बैठकर नया चावल ग्रहण किया। मान्यता है कि देवी को अर्पित किए बिना नई फसल का सेवन नहीं किया जाता।द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - गरीबी को मात देकर डॉज़्टर बनने की राह पर पांच भाई-बहन, पिता ने केरल में मजदूरी कर पढ़ाया नुआखाई शज़्द दो स्थानीय शज़्दों से मिलकर बना है। इसमें 'नुआ' का अर्थ नया और 'खाई' का अर्थ खाना या ग्रहण करना है। इस तरह नुआखाई का शाज़्दिक अर्थ नई फसल का भोजन करना है। यह त्योहार किसानों द्वारा उपजाए गए नए धान का स्वागत करने और अच्छी फसल के लिए प्रकृति एवं देवी-देवताओं के प्रति आभार जताने का अवसर माना जाता है। यह पर्व ओडिया महीने भाद्रबा के शुज़्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार, गणेश चतुर्थी के अगले दिन नुआखाई का आयोजन होता है। पश्चिमी ओडिशा में इसका महत्व केवल कृषि उत्सव तक सीमित नहीं है। यह परिवार, समाज, परंपरा, आपसी मेल-मिलाप और सांस्कृतिक पहचान का भी बड़ा

पर्व है। संबलपुर के साथ बरगढ़, बलांगीर, सुबरनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बौध और देवगढ़ सहित पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में त्योहार की रौनक दिखाई दी। सुबह से मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना का क्रम चला। लोग पारंपरिक परिधान पहनकर एक-दूसरे के घर पहुंचे और नुआखाई जुहार कहकर शुभकामनाएं दीं। नुआखाई के दौरान परिवार के छोटे सदस्य अपने माता-पिता, दादा-दादी और अन्य बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस परंपरा को 'नुआखाई जुहार' कहा जाता है। समान उम्र के लोग एक-दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। पर्व पर पुराने मतभेद भुलाकर रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की परंपरा भी रही है।

रोजगार, शिक्षा या कारोबार के लिए प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग नुआखाई के अवसर पर अपने पैतृक गांव और घर लौटते हैं। इससे संयुक्त परिवारों को एक साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। गांवों में सामूहिक भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पारंपरिक गीत, नृत्य और वाद्ययंत्र त्योहार के माहौल को और आकर्षक बनाते हैं। इस अवसर पर घरों में नए चावल के साथ विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पकवान तैयार किए गए।

परिवार की महिलाएं कई दिन पहले से त्योहार की तैयारी में जुट गई थीं। घरों की सफाई, नए कपड़ों की खरीदारी और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई। ग्रामीण बाजारों में नए कपड़ों, मिठाइयों, फलों, सज़्जियों और पूजा सामग्री की मांग बढ़ी। कृषि आधारित परिवारों के लिए यह पर्व नई उपज के प्रति सज़्मान की भावना को प्रदर्शित करता है। किसान अपनी पहली फसल देवी को समर्पित कर यह स्वीकार करते हैं कि खेती केवल मानवीय मेहनत पर निर्भर नहीं है। मिट्टी, पानी, वर्षा, सूर्य और प्रकृति का संतुलन भी अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। इसलिए नुआखाई को प्रकृति और मनुष्य के संबंध का पर्व भी कहा जाता है। इस वर्ष अच्छी वर्षा और बेहतर कृषि परिस्थितियों ने त्योहार के उत्साह को और बढ़ा दिया। किसानों ने आने वाले कृषि मौसम में अच्छी उपज और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कई स्थानों पर किसान नए धान की बालियां लेकर स्थानीय देवी के मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटा गया। ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग की जानकारी के अनुसार, नुआखाई मां समलेश्वरी मंदिर के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। इस अवसर पर किसान अपनी जमीन की पहली उपज व्यक्तिगत उपयोग से पहले देवी को अर्पित करते हैं। मां समलेश्वरी को पश्चिमी ओडिशा की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। समलेश्वरी मंदिर की आधिकारिक जानकारी में भी नुआखाई को पूरे पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख पर्व बताया गया है। त्योहार के अगले चरण में विभिन्न स्थानों पर 'नुआखाई भेंटघाट' कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोग एक स्थान पर जुटकर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। लोक कलाकार पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को क्षेत्र की भाषा, संगीत, पहनावे और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। नुआखाई आधुनिकता के बीच पश्चिमी ओडिशा की कृषि और सामाजिक परंपरा को जीवित रखने वाला पर्व है। नई फसल के भोग से शुरू हुआ उत्सव बुजुर्गों के आशीर्वाद, पारिवारिक भोज और सामुदायिक मिलन के साथ आगे बढ़ा। खेतों से लेकर मंदिरों और घरों तक लोगों ने नुआखाई जुहार के साथ खुशहाली और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया।

स्वाभिमान अंचल में 52 आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत खराब

चित्रकोंडा १९/०९ (संवाददाता): मल्कानगिरी ज़िले के इस ज़्लॉक में %स्वाभिमान अंचल% की 18 पंचायतों में मौजूद 180 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 52 के पास अपनी इमारतें नहीं हैं। इस वजह से बच्चों को कज़्युनिटी सेंटर, स्कूलों और निजी घरों के बरामदों में प्री-स्कूल ज़्लास में जाना पड़ता है। आंद्रापल्ली पंचायत के अंतर्गत जंत्री और पापुल्लुर पंचायत के अंतर्गत गुरालुर में आंगनवाड़ी केंद्र कज़्युनिटी सेंटर से चल रहे हैं, जबकि आंद्रापल्ली पंचायत में मुकुडीपल्ली और बडापाडा पंचायत में डोलियाज़्बा में केंद्र सालों से स्कूलों से चल रहे हैं। नागुलुर और हंतलगुडा केंद्रों में आंगनवाड़ी वर्कर के पद खाली पड़े हैं, वहीं ज़्लॉक के 72 आंगनवाड़ी केंद्रों में लंबे समय से रसोइए (कुक) के पद खाली हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस वजह से बच्चों की प्री-स्कूल शिक्षा पूरी तरह से बाधित हो रही है।

शिक्षण और कक्षा संसाधन यात्रा की गाइड और यात्रा की जानकारी स?थानीय समाचार पापरमेटला पंचायत के अंतर्गत तांतागुडा गांव में, आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 15 सालों से एक निजी घर के बरामदे से चल रहा है। यह केंद्र 2011 में खोला गया था, लेकिन अभी तक कोई पक्की इमारत नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर पार्वती हंतल अपने पैतृक घर के बरामदे में मिट्टी के फ़र्श पर बैठाकर 35 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम में भी वहां ज़्लास में जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कई बार द्धष्टष्ठस् सुपरवाइज़र, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेज़्ट ऑफ़िसर और ज़्लॉक अधिकारियों का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया है। लगभग तीन-चार साल पहले, स्थानीय ठेकेदार बीजू खिल ने एक स्कूल के पास आंगनवाड़ी इमारत का निर्माण शुरू किया था। हालांकि, नींव का काम पूरा होने के बाद काम रोक दिया गया। ग्रामीणों कमला श्रीगम, मिश्रा खिल, मणि हंतल, एकामा खिल और घेनु हंतल ने कहा कि जूनियर इंजीनियर और ज़्लॉक अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला।

सुपरवाइज़र कुमारी नायक ने कहा कि निजी बरामदों में ज़्लास चलाना मुश्किल होता है ज़्योंकि केंद्र के पास अपनी इमारत नहीं है। चित्रकोंडा की ष्टष्ठक्क प्रमिला देवता ने कहा कि कई आंगनवाड़ी केंद्रों में इमारतों की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को बार-बार सूचित किया गया है। ज़्लॉक जूनियर इंजीनियर कमलेश नायक ने बताया कि ज़िला और ज़्लॉक अधिकारियों के कहने पर निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन इसके लिए कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फ़ंड की कमी के कारण कॉन्ट्रैज़्टर ने काम रोक दिया है और इस मामले में कार्रवाई के लिए मलकानगिरी ज़िले के इंटीग्रेटेड महिला एवं बाल विकास विभाग को एक पत्र भेजा गया है। नागुलुर और हंतालागुडा के दो-द्धष्ट में भी वर्कर के पद खाली पड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके अलावा, ज़्लॉक के 26 सेंटरों में रसोइए के पद भी सालों से खाली हैं।

आरएसपी में संविदा श्रमिकों के लिए राजभाषा पखवाड़ा के तहत मनाया गया प्रश्नोज़री प्रतियोगिता

राउरकेला १९/०९ (संवाददाता): सेल के राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में 12 सितंबर 2026 को परियोजना सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल और सीपीटीआई मे राजभाषा पखवाड़ा के पालन के लिए दो राजभाषा प्रश्नोज़री प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 140 से अधिक संविदा श्रमिकों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। ये कार्यक्रम जनसंपर्क -राजभाषा विभाग द्वारा दो हज़्ते तक चलने वाले राजभाषा पखवाड़ा समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित किए गए थे। प्रतियोगिताओं के दौरान महाप्रबंधक (एचआर), नॉन-वर्क्स, श्री जी. आर. दास और उप प्रबंधक (एचआर-सीएलसी), सुश्री इतिश्री साहू मौजूद थीं। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक (जनसंपर्क), श्री अनिल कुमार झा और जनसंपर्क -राजभाषा टीम ने किया। राजभाषा पखवाड़ा के हिस्से के रूप में, राजभाषा इकाई ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और पूरे संयंत्र में इसके महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की है। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना और आरएसपी में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक, सहभागी वातावरण को बढ़ावा देना है।

ओडिशा पुरुष सिटिंग वॉलीबॉल टीम के लिए आर.एस.पी. के दो कर्मचारी चयनित

राउरकेला १९/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के केंद्रीकृत विद्युत अनुरक्षण विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट, श्री रुद्र नारायण साहू और विद्युत वितरण विभाग के जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट, श्री परेश कुमार मोहांतो जैसे दो कर्मचारियों का चयन वर्ष 2026 की तीसरी फेडरेशन कप सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए ओडिशा पुरुष सिटिंग वॉलीबॉल टीम हेतु किया गया है। चयन प्रक्रिया पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ ओडिशा (पी.एस.ए.ओ.) द्वारा शुरू की गई थी। चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 27 सितंबर, 2026 तक इरोड, तमिलनाडु में किया जाना निर्धारित है। दरगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रुद्र नारायण साहू और श्री परेश कुमार मोहांतो चयन समिति द्वारा चयनित 14 खिलाड़ियों में शामिल हैं। खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन, तकनीकी दक्षता, फिटनेस, अनुशासन तथा समग्र उपयुक्तता के आधार पर किया गया। टीम के अंतिम गठन के बाद खिलाड़ियों की व्यवस्थित तैयारी के लिए 8 से 22 सितंबर, 2026 तक भुवनेश्वर के नयापल्ली स्थित इंडोर स्टेडियम में 15 दिवसीय कोचिंग-सह-तैयारी शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में व्यवस्थित प्रशिक्षण, टीम समन्वय, शारीरिक क्षमता संवर्धन तथा चैंपियनशिप के लिए व्यापक तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ओडिशा के आदिवासी परिवार की प्रेरणादायक कहानी

फूलबानी १९/०९ (संवाददाता): दो बहनों और उनकी चचेरी बहन ने प्रतिष्ठित ह्वश्वश्वञ्ज परीक्षा पास कर ली है और ओडिशा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पा लिया है। इससे कंधमाल जिले का एक गरीब आदिवासी परिवार चर्चा में आ गया है, जिसके पांच बच्चे अब डॉज़्टर बनने की राह पर हैं। ऐसे परिवार में पले-बढ़े बच्चे, जहाँ घर चलाने वाले अकेले व्यक्ति एक प्रवासी मज़दूर हैं जो थोड़ी सी ज़मीन पर खेती भी करते हैं, उन्हें बहुत कम उम्र में ही पता चल गया था कि शिक्षा ही उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता है। और सफलता के लिए उन्हें लगन और दृढ़ता की ज़रूरत होगी। डारिंगबाड़ी के पहाड़ी और जंगली इलाके में बसे सिकबाड़ी गाँव के ज़रुशी नाइक (76) और अनुसूया (62) के सबसे बड़े बेटे बिभीषण नाइक (25) ने सबसे पहले NEET पास किया।

उन्हें कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नाइक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और अब वे उसी संस्थान में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनकी बहन मोनलिसा (23) उसी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा हैं। अब, सुनेमी (20), आश्रिया (18) और मीनाक्षी (19) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और पुरी, बलांगीर और भवानीपटना के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। मीनाक्षी (19), ज़रुशी के छोटे भाई जिशिया प्रधान की बेटी हैं। हालाँकि, बचपन से ही ज़रुशी और अनुसूया ने ही उनकी परवरिश की है। अनुसूया ने एस्बेस्टस की छत और मिट्टी की दीवारों वाले अपने घर में बैठे हुए कहा, सभी मेरे बच्चे हैं। हमारे परिवार में नौ सदस्य हैं। मेरे दो छोटे बेटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों ने डारिंगबाड़ी में स्कूली शिक्षा पूरी की और नयागढ़ में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की।द्यह्यश बिभीषण नाइक, जो अपने परिवार में डॉज़्टर की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति बनने वाले हैं, ने

कहा, मैंने अपनी छोटी बहन मोनलिसा को ह्वश्वश्वञ्ज परीक्षा के लिए गाइड किया, और उसने आसानी से इसे पास कर लिया। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और मैं बाकी तीनों को कुछ दिनों की कोचिंग के लिए बेरहामपुर शहर ले गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया, तो उन्होंने कहा, मेरे पिता मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मैं इलाके में बच्चों को पढ़ाता हूँ और अब तक मैंने अपनी और अपने भाई-बहनों की पढ़ाई के लिए 6 लाख रुपये का लोन लिया है। विभीषण ने बताया कि उनके सभी भाई-बहनों को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है।

मीनाक्षी कहती हैं, हमने अपने माता-पिता का संघर्ष देखा है। वे हमारी प्रेरणा हैं। हमने उनसे सादा जीवन और उच्च विचार का मतलब सीखा है। कभी-कभी हमें भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन हमने हमेशा अपनी पढ़ाई में बेहतर करने की कोशिश की। ज़रूशी खुद सिर्फ़ दूसरी ज़्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन वे शिक्षा का महत्व समझते थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत की ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। वे परिवार की छोटी सी ज़मीन पर धान, अदरक और हल्दी उगाकर गुज़ारा करते हैं। कभी-कभी, वे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए दूसरे राज्यों में मज़दूरी करने भी जाते हैं। इसके अलावा, परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा रहा है। ज़रूशी ने PTI को बताया, मुझे नहीं पता कि वे ज़िंदगी में कैसे सफल हुए... मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने पाँचों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना है, जो अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कुछ लोन लिए हैं, लेकिन बच्चों को किताबों और दूसरी चीज़ों के लिए और पैसों की ज़रूरत है। मेडिकल की पढ़ाई महंगी होती है।उनकी पत्नी अनुसूया, जिन्होंने खुद कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, भले ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की बातें न समझती हों, लेकिन वे यह ज़रूर जानती हैं कि उनकी शिक्षा का ज़्या मतलब हो सकता है — पीढ़ियों से परिवार पर छाई गरीबी से बाहर निकलने का एक मौका। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरा काम परिवार के लिए खाना बनाना और बच्चों को अनुशासन में रखना है। इस साल MBBS कोर्स में दाखिला लेने वाली सुनेमी प्रधान ने कहा, हमें ज़िंदगी की शुरुआत में ही पता चल गया था कि गरीबी ज़्या होती है। माता-पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी ज़रूरतें अपनी सीमा के अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। आश्रिया ने कहा, हमने अपने पिता को बहुत परेशान देखा है कि वे हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और हम हालात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ज़रूशी के भाई जिशिया प्रधान ने राज्य सरकार से परिवार का बोझ कम करने के लिए कुछ मदद की अपील की। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे डॉज़्टर बनकर इलाके के लोगों की सेवा करेंगे। पूरे गाँव को उन पर गर्व है। गाँव से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए भी, ये बच्चे उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं जिसने उन्हें बनाया है; वे ज़रूशी का हाथ बंटाते हुए परिवार के खेत में काम करते हैं और मवेशियों की देखभाल भी करते हैं।